इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

Committed to professional excellence

IIBF VISION

खंड संख्या 14 | अंक संख्या 8 | मार्च 2022 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन:

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---------- 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 3
विनियामक के कथन---------- 3
आर्थिक संवेष्टन ---------- 4
नयी नियुक्तियाँ---------- 5
विदेशी मुद्रा---------- 5
शब्दावली---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -------- 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां---------- 7
संस्थान समाचार---------- 7
नयी पहलकदमी---------- 9
बाजार की खबरें ---------- 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य विशेषताएँ

गवर्नर की अध्यक्षता वाली छ: सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 8 से 10 फरवरी, 2022 तक आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे निम्नानुसार थे :

- पुनर्खरीद (repo) दर एवं प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर को 4% और 3.3% पर अपरिवर्तित रखा गया।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर को 4.25% पर रखा गया।
- आगामी राजकोषीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अनुमान 7.8% रखा गया, विद्यमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3% तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 4.5% रखा गया।
- घटते-बढ़ते परिपक्वता कालों (varying tenors) के परिवर्ती दर (variable rate) वाले पुनर्खरीद परिचालनों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) अनुरक्षण चक्र के भीतर रखा जाएगा।
- 14 दिनों के परिपक्वता काल वाली परिवर्ती (variable) दर पुनर्खरीदों तथा परिवर्ती दर प्रति-पुनर्खरीदों को मुख्य चलनिधि प्रबंधन साधन के रूप में परिचालित किया जाएगा।
- स्थिर दर प्रति-पुनर्खरीद और सीमांत स्थायी सुविधा परिचालनों को कमतर समयावधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि को कठोर बनाने हेतु स्थिर दर वाली प्रति-पुनर्खरीद, सीमांत स्थायी सुविधा परिचालनों के लिए समय संबंधी सुविधा को कम किया

स्थिर दर वाली प्रति-पुनर्खरीद सुविधा के अधीन चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) परिचालनों के कामकाज के समय को 1 मार्च, 2022 से वैश्विक महामारी के पूर्व वाले समय-खांचों (time-slots) पर वापस ला दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय चलनिधि को कठोर बनाने के अपने उपायों के एक अंग के रूप में लिया है। वैश्विक महामारी के दौरान पूरे दिन चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये दोनों ही परिचालन 0900 बजे से 2359 बजे तक उपलब्ध कराये जा रहे थे। हालांकि, अब वे केवल 1730 बजे से 2359 बजे तक ही उपलब्ध होंगे। अन्य सभी शर्तों एवं निबंधनों को अपरिवर्तित्त रखा गया है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

ऋण व्युत्पन्नी लेनदेनों को भारतीय रिजर्व बैंक से मास्टर निर्देश प्राप्त हुये

9 मई, 2022 से काउंटर पर किए जाने वाले लेनदेनों के बाजारों में तथा भारत में स्थित मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों में किए जाने वाले ऋण व्युत्पन्नी (credit derivative) लेनदेनों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुख्य/मास्टर निर्देशों का पालन करना होगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमन, 2019 के अधीन कारपोरेट बाँड़ों और डिबेंचरों में निवेश करने के पात्र निवासियों एवं अनिवासियों को ऋण व्युत्पन्नी बाजार में सहभागिता करने की अनुमति होगी।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों को छोडकर), भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक निश्चित आकार वाले बैंकेतर ऋणदाताओं और सरकार द्वारा संचालित भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Exim Bank), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास

बैंक (NABARD), राष्ट्रीय आवास (NHB) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ मिलकर ऋण व्युत्पन्नियों (credit derivatives) के बाजार-निर्माताओं (market makers) के रूप में कार्य करेंगे। ये बाजार-निर्माता प्रयोक्ताओं को खुदरा या

गैर-खुदरा के रूप में वर्गीकृत करेंगे। गैर-खुदरा प्रयोक्ताओं में गैर बाजार-निर्माता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों, पारस्परिक (Mutual) निधियों, वैकल्पिक निवेश निधियों, 500 करोड़ रुपए से अधिक की निवल मालियत वाली निवासी कंपनियों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का समावेश होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आकस्मिक स्वस्थ्य सेवाओं के लिए चलनिधि सुविधा 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी

वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मई, 2021 को कोविड-19 से संबन्धित स्वास्थ्य-रक्षा मूलभूत सुविधा और सेवाओं के लिए तीन वर्ष के परिपक्वता कालों तक की सदा-सुलभ (on tap) पूंजी उपलब्ध कराने हेतु पुनर्खरीद दर पर एक चलनिधि सुविधा आरंभ की थी। अब शीर्ष बैंक ने इस सुविधा को 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनर्जक आस्ति मानदंडों को कार्यान्वित करने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छः माह का और समय दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उस नियम को कार्यान्वित करने के लिए नवंबर, 2021 में 31 मार्च, 2022 तक का समय दिया था जिसमें केवल ब्याज और मूलधन का सम्पूर्ण भुगतान किए जाने के बाद ही अशोध्य ऋणों का मानक आस्ति के रूप में कोटि-उन्नयन किया जा सकता था। शीर्ष बैंक ने इस अंतिम अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया है। ऋणदाता से एक से अधिक ऋण सुविधा का उपयोग करने वाले उधारकर्ताओं को उस खाते का अनर्जक आस्ति श्रेणी से मानक आस्ति श्रेणी में कोटि-उन्नयन करने हेतु सभी ऋण सुविधाओं के लिए ब्याज और मूलधन के समस्त पिछले बकाए की चुकौती करनी होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में स्थित बैंकों को विदेशी मुद्रा में तय रुपया व्युत्पन्नियाँ प्रदान करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्य-अन्वेषण में सुधार लाने, ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजार को गहनता प्रदान करने और तटवर्ती (onshore) एवं अपतटीय (offshore) बाज़ारों में संवर्गीकरण को समाप्त करने के लिए भारत में स्थित बैंकों को अपतटीय विदेशी मुद्रा में तय एक-दिवसीय सूचकांकित अदला-बदली (FCS_OIS) दर प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है। अपतटीय विदेशी मुद्रा में तय एक-दिवसीय सूचकांकित अदला-बदली एक दिवसीय मुंबई अन्तर-बैंक एकमुश्त (outright) दर (MIBOR) बेंचमार्क पर आधारित होगी। बैंक इन लेनदेनों को तटवर्ती बाजार के कामकाज के समय से भिन्न समय में कर सकते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से सितंबर, 2025 तक कोर वित्तीय सेवा समाधान कार्यान्वित करने के लिए कहा गया

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अक्तूबर, 2022 के दिन 10 और उससे अधिक ''नियत स्थलीय सेवा सुपुर्दगी एककों'' वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों –मझोली परत वाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों –उच्चतर परत वाली से 30 सितंबर, 2025 से अनिवार्य रूप से ''कोर वित्तीय सेवा समाधान'' (CFSS) कार्यान्वित करने हेतु कहा गया है। उक्त कोर वित्तीय सेवा समाधान से डिजिटल प्रस्तावों (offerings) और सर्वत्र/सर्वदा (anyehere/anytime) सुविधा वाले उत्पादों एवं सेवाओं से संबन्धित लेनदेनों में सीवन-रहित ग्राहक अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराये जाने की आशा है। यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यों के एकीकरण को भी समर्थ बनाएगी, केंद्रीकृत डेटाबेस एवं लेखांकन अभिलेख/रिकार्ड उपलब्ध कराएगी तथा आंतरिक प्रयोजनों और विनियामक रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सृजित करने में समर्थ होगी।

विनियामक के कथन

बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से पूंजी आवर्धन जारी रखने, उपयुक्त सुरक्षित भंडार निर्मित करने के लिए कहा गया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से भावी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए पूंजी आवर्धन जारी रखने तथा उपयुक्त सुरक्षित भंडार निर्मित करने का आह्वान किया है।

भारत की वित्तीय प्रणाली वैश्विक महामारी के दौरान आघात-सह बनी रही। वास्तव में अब वसूली के गति पकड़ लेने तथा निवेश गतिविधि के बढ जाने के कारण वह ऋण की मांगें पूरी करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। उच्चतर पूंजी पर्याप्तता, घटी अनर्जक आस्तियों, उच्चतर प्रावधानीकरण सुरक्षा तथा बढ़ी लाभप्रदता के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के तुलनपत्र तुलनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ हैं।

इसके बावजूद गवर्नर ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को आत्मतुष्ट होने और अपनी निगरानी में ढील देने के विरुद्ध चेतावनी दी है। इसके बजाय उन्होंने परिवर्धित रूप से गतिशील एवं अनिश्चित आर्थिक वातावरण में उन्हें अपने कारपोरेट अभिशासन एवं जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को और अधिक सुदृढ़ करने की अच्छी सलाह दी है।

क्रिप्टो मुद्राओं को समर्थन देने से एक मुद्रा के रूप में रुपया कमजोर पड़ेगा, नियंत्रक मुद्रा आपूर्ति को कठिन बनाएँ: टी॰ रबी शंकर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर ने कहा है कि क्रिप्टो मुद्राओं/करेंसियों का समर्थन करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे एक मुद्रा के रूप में रुपए की भूमिका कमजोर पड जाएगी और मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने की प्राधिकारियों की योग्यता प्रभावित होगी। उन्होंने इसके पीछे निहित कारण का उल्लेख करते हुये कहा कि क्रिप्टो करेंसियाँ करेंसियाँ अथवा वित्तीय आस्तियां या स्थावर सम्पदा अथवा यहाँ तक कि डिजिटल आस्तियां भी नहीं होतीं तथा किसी ऐसी चीज को विनियमित करना संभव नहीं है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए क्रिप्टो करेंसियाँ स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रभावी ''डालरीकरण'' हो सकता है।

डालरीकरण से अभिप्राय है ऐसी अद्भुत घटना जिसमें अमरीकी डालर का उपयोग किसी दूसरे देश की घरेलू मुद्रा के अतिरिक्त अथवा उसके बजाय किया जाता है।

वैसा होने की स्थिति में मौद्रिक नीति का गैर-रुपया मुद्राओं अथवा भुगतान लिखतों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जिससे मुद्रा आपूर्ति या ब्याज दरों को नियंत्रित करने हेतु प्राधिकारियों की योग्यता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त, चूंकि क्रिप्टो करेंसी भुगतान पूंजीगत लेखे के विनियमन की परिधि से बाहर किए जा सकते हैं, यह पूंजी प्रवाहों पर नीतिगत नियंत्रण और इसप्रकार पूंजीगत लेखा प्रणाली की ईमानदारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि का उपचय और विनिमय दर प्रबंधन गंभीर रूप से प्रभावित होंगे तथा गंभीर स्थूल-आर्थिक स्थिरता के मुद्दे उभर कर सामने आ सकते हैं।

आर्थिक संवेक्षण

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट जनवरी, 22 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 2020-21 की उसी अवधि के 36.26 लाख करोड़ रुपए के समक्ष 38.22 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 5.4% की वृद्धि दर्शाता है।
- मासिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जनवरी, 22 के लिए 12.96% पर रही।
- जनवरी, 22 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 6.01% रहा।
- दिसंबर, 2021 में कृषि क्षेत्र को ऋण सहायता में 14.5% की दृढ़निश्चयी तगड़ी वृद्धि परिलक्षित हुई।
- पीएमआई विनिर्माण सूचकांक 54 के विस्तारात्मक संस्तर में बना रहा। हालांकि, पीएमआई सेवा जनवरी, 2022 में परिणामी रूप से घटकर 51.5 के रूप में छ : माह के न्यून स्तर पर पहुँच गया।
- दिसंबर, 2021 माह के लिए 2011-12 के आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान 138 रहे, जो दिसंबर,

2020 की तुलना में 0.4% अधिक थे।

- दिसंबर, 2021 में आठ मुख्य उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 141.3 रहा, जिसमें दिसंबर, 2020 के सूचकांक की तुलना में 3.8% की वृद्धि दर्ज हुई।
- दिसंबर, 2021 में उद्योग को ऋण वृद्धि में वर्षानुवर्ष 7.6% की तीव्र बढ़ोतरी हुई।
- जनवरी, 2022 में भारत के व्यापारिक निर्यात में क्रमश: जनवरी, 2021 और जनवरी 2020 के मुक़ाबले 25.3 और 33.4% की वृद्धि दर्ज हुई।
- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-sec.) का प्रतिफल 28 आधार अंकों की कमी के साथ जनवरी, 2022 में 6.7% रह गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट : कोविड की तीसरी लहर के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से पुनरुत्थान हो रहा है

अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अपेक्षाकृत कम अनिष्टकर कोविड की तीसरी लहर से बाहर आते हुये भारत की अर्थव्यवस्था में संवेग आ रहा है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि टीकाकरण की त्वरित गति और सामान्य आर्थिक स्थित पारिवारिक आय एवं व्यय से संबन्धित बेहतर संभावनाओं के कारण तीसरी लहर में उपभोक्ता एवं व्यवसाय क्षेत्र का विश्वास अत्यधिक आघात-सह रहा। फरवरी, 2022 में गतिशीलता संकेतक सुधर कर वैश्विक महामारी-पूर्व वाले स्तर पर पहुँच गए तथा कंपनियों द्वारा जोरदार नियोजन योजनाएँ तैयार किए जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की दर में कमी आ गई। सुदृढ़ माल और सेवा कर वसूली, चुंगी वसूलियाँ और आई-वे बिल सृजन ये सभी पुनरुत्थान का संकेत देते हैं। मांग प्राचलों (parameters) एवं उपभोक्ता और व्यवसाय क्षेत्र के विश्वास मे वृद्धि संबंधी आशावादिता के परिणामस्वरूप विनिर्माण और सेवा क्षेत्र विस्तारवादी स्थिति में बने हुये हैं। सरकार द्वारा घोषित उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों के कारण कृषि क्षेत्र भी उत्साही (upbeat) स्थिति में है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री प्रलय मण्डल	उप प्रबंध निदेशक, सीएसबी बैंक
सुश्री माधवी पुरी बुच	अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 फरवरी, 2022 के दिन करोड रुपए	25 फरवरी, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. **कुल प्रारक्षित निधियाँ**	4755726	631527
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4253494	564832
1.2 सोना	319800	42467
1.3 विशेष आहरण अधिकार	143381	19040
1.4 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	39051	5187

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2022 माह के लिए अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) जमाराशियों के लिए लागू होने वाली वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की न्यूनतम दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	0.05
जीबीपी	0.4451
यूरो	-0.576
जापानी येन	-0.017
कनाडाई डालर	0.1900
आस्ट्रेलियाई डालर	0.10
स्विस फ्रैंक	-0.718465
न्यूजीलैंड डालर	1.00
स्वीडिश क्रोन	-0.093
सिंगापुर डालर	0.2791
हांगकांग डालर	0.03075
म्यामर रुपया	1.75

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

नियत स्थलीय सेवा सुपुर्दगी एकक

नियत स्थलीय सेवा सुपुर्दगी एकक (Fixed Point Service Delivery Unit) परिचालन का एक ऐसा स्थान होता है जहां से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थीकरण का व्यवसाय किया जाता है और जो या तो उनके अपने स्टाफ द्वारा या फिर बाहर से रखे गए एजेन्टों द्वारा संचालित (manned) होता है। यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नाम के साथ एकसमान चिन्ह (signage) वहन करता है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। उन प्रशासनिक कार्यालयों और बैक आफ़िसों को नियत स्थलीय सेवा सुपुर्दगी एकक नहीं माना जाना चाहिए जिनका ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अंतरापृष्ठ (interface) नहीं होता।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्राप्यराशि आवर्त अनुपात (Recievables Turnover Ratio)

प्राप्यराशि आवर्त अनुपात किसी कंपनी की अपनी प्राप्य राशियों अथवा उसके ग्राहकों द्वारा देय धनराशि को वसूल करने में उसकी प्रभावशीलता की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त एक लेखांकन माप होता है। इस अनुपात से इस बात का पता लगता है कि कोई कंपनी अपने ग्राहकों को दी जाने वाली उधार सुविधा का कितनी अच्छी तरह उपयोग और उसका प्रबंधन करती है तथा वह अल्पावधिक ऋण कितनी शीघ्रता से वसूल किया जाता है अथवा उसका भुगतान किया जाता है। इस अनुपात का निर्धारण करने का सूत्र है लेनदारी लेखों/खातों का आवर्त = औसत लेनदारी लेखे/खाते/निवल उधार विक्री

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च/अप्रैल, 2022 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
प्रमाणित ऋण व्यवसायिक	11 से 13 मार्च, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
व्यावसायिक नीतिशास्त्र एवं कार्पोरेट अभिशासन (कार्यशाला)	14 मार्च, 2022	
व्यापार वित्त (साख पत्र, बैंक गारंटियाँ आस्थगित भुगतान गारंटियाँ, एसबी एलसीज और व्यापार ऋण - घरेलू एवं विदेशी दोनों)	14 से 15 मार्च, 2022 तक	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	15 से 17 मार्च, 2022 तक	
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक	22 से 24 मार्च, 2022 तक	
प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिक	6 से 8 अप्रैल, 2022 तक	

संस्थान समाचार

डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र/ मिश्रित परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम

डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र/मिश्रित परीक्षाओं की संशोधित तिथियाँ , जो 20 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च , 2022 को आयोजित की जानी थीं, घोषित कर दी गई हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्णन मानदंड में संशोधन

डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नीतिशास्त्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि के अधीन अंतिम मूल्यांकन/परीक्षण हेतु उत्तीर्णन अंकों को 70 से संशोधित करके 60 कर दिया गया है। यह 1 मार्च, 2022 को या उसके बाद आत्म-समगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कराये जाने वाले पंजीकरणों पर प्रभावी होगा।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक का विमोचन किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने दिसंबर, 2021 तक अद्यतन की हुई "बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक" का विमोचन किया। यह सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों और बैंकिंग एवं वित्त के विषय-क्षेत्र के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये विनियामक परिवर्तनों की एक ऐसी व्यापक सार-पुस्तिका है जिसमें पाठक को हितकर वाचन अनुभव दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए

महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरणों, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा लेखों का समावेश है। उक्त पुस्तक पेपरबैक के रूप में और एक उद्दीपक (kindle) संस्करण, दोनों ही रूपों में अमैजान पर उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से 11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों

के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकरों की अच्छी-ख़ासी संख्या में उपस्थिति रही।

जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज़ (JBIMS) के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए रणनीतिक नेतृत्व पर उन्नत कार्यक्रम को संयुक्त रूप से प्रमाणित करने हेतु जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के साथ सहयोग किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन के भविष्य के लिए वहनीय विजन सृजित करने हेतु रणनीतिक चिंतन एवं सामर्थ्य को बढ़ाना है। उक्त

कार्यक्रम केवल सप्ताहांत में (शनिवारों और रविवारों कॉ) संचालित किया जाने वाला 30 घंटो का (5 दिवसीय) कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने

के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक

संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून, 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थाई तौर पर निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/

दिसम्बर, 2022 दौरान आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून, 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखेँ।

जीएआरपी संयुक्त राज्य अमेरिक द्वारा वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) परीक्षा हेतु पंजीकरण

संस्थान ने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 300 अमरीकी डालर के बट्टागत शुल्क पर वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) पाठ्यक्रम उपलब्ध करने के लिए ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल्स (GARP) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उक्त वित्तीय जोखिम एवं विनियमन पाठ्यक्रम जोखिम प्रबंधन यथा- ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम तथा आस्ति एवं देयता प्रबंधन (ALM) जैसे मुख्य पहलुओं पर विहगावलोकन प्रदान करता है। पंजीकरण सुविधा 1 अपराइलसे 15 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध रहेगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखेँ।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने सब के लिए ई-शिक्षण की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम- सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जनवरी – मार्च, 2022 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "दबावग्रस्त आस्तियों का प्रभावी समाधान (Effective resolution of stressed assets)"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक

परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

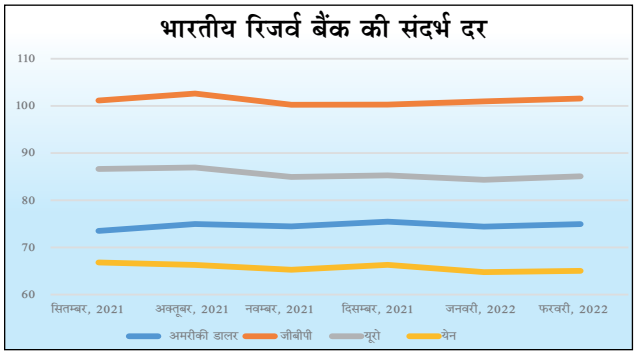

स्रोत: एफबीआईएल

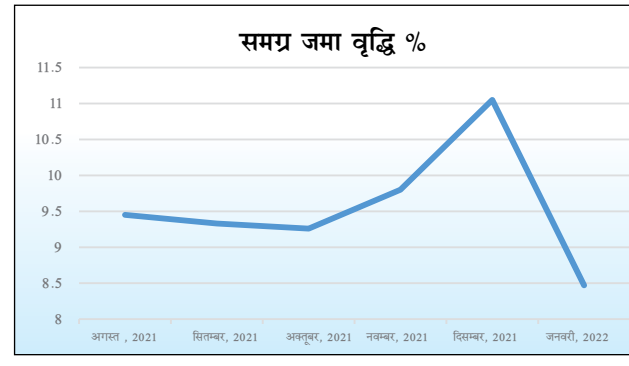

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2022

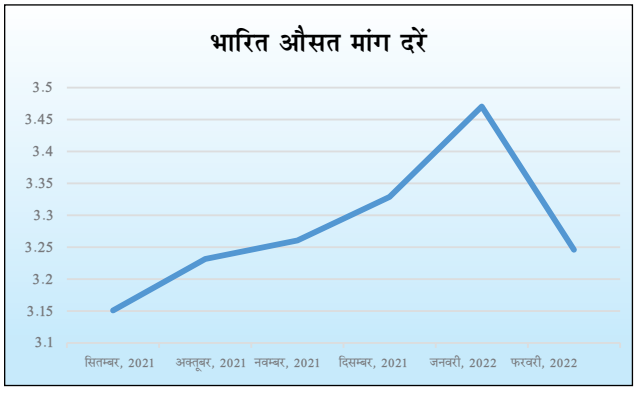

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

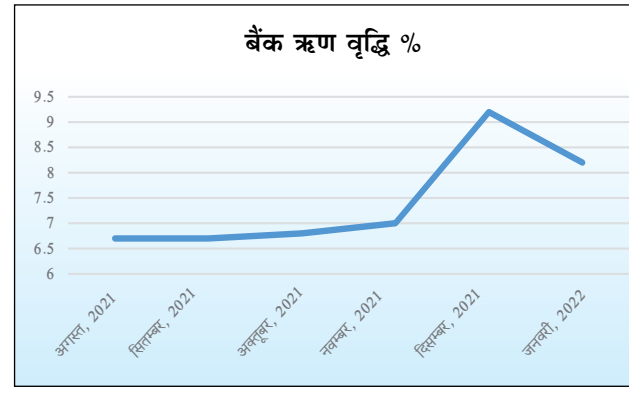

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

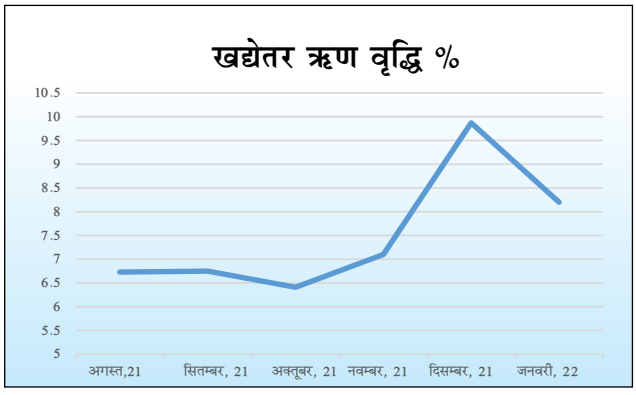

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2022

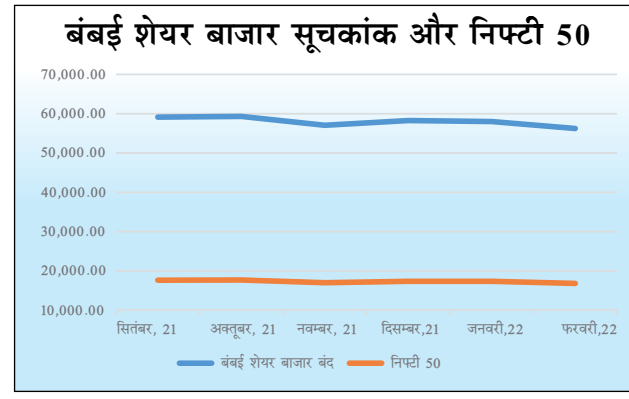

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

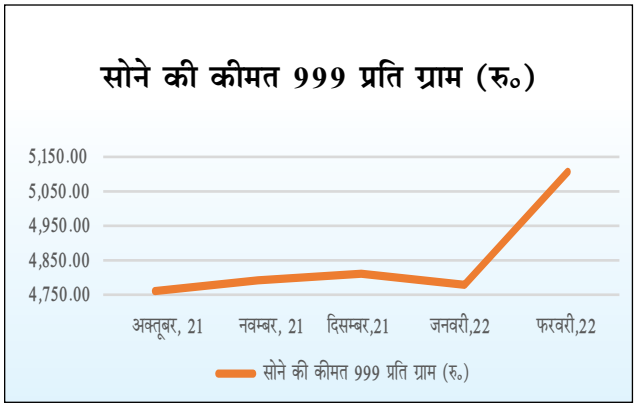

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : बिश्व केतन दास

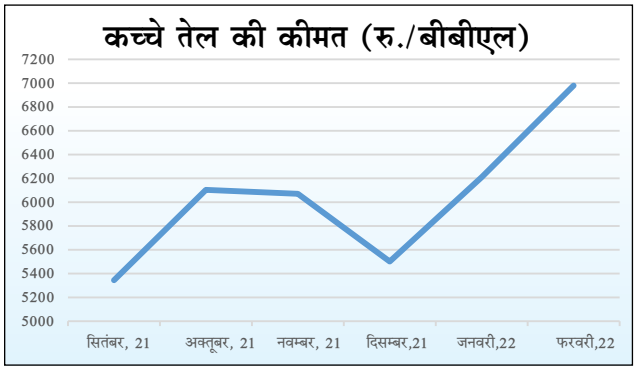

स्रोत: पीपीसीए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-6850 7000
फैक्स : 91-22-2503 7332
वेबसाइट : www.iibf.org.in